RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 273
दि. 04.02.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, एनडीए सांसदों ने दी बधाई

नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए स्वागत किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक डील के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ में कटौती की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया।

(एजेंसी)।

नई दिल्लीः संसद परिसर में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। सभी सांसदों ने पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक डील के लिए बधाई दी। बता दें कि सोमवार की रात डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाए गए 25 प्रतिशत के टैरिफ में कटौती कर 18 फीसदी कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। वहीं, इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी औपचारिक रूप से स्वागत किया गया।

नितिन नवीन का भी जोरदार स्वागत

संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन उपस्थित हैं। इस बैठक में नितिन नवीन का भी जोरदार स्वागत किया गया। संसदीय दल की बैठक में इन दो नेताओं के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं।

इ ळअइडडछअरढडठरडफएऊ छक्ठङर डव टअ छक्ङए
टळ डल्ल'ल्ली रस्ज्ञ्ञ्ञ'२
ऋ८ ६३ँ ट'८२ अ१'ल्लीर

सोमवार रात डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में कटौती की घोषणा की थी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को एक बड़ा ऐलान करते हुए भारत पर लगे टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। यह जानकारी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर एक पोस्ट के जरिए दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ की आबादी की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प को हार्दिक धन्यवाद।

उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं।

ट्रंप ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की थी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया। ट्रंप ने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम छह फरवरी को प्रसारित होगा

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शुक्रवार को प्रसारित होने वाले विशेष 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को देखने के लिए मंगलवार को आमंत्रित किया, जिसमें भारत के युवाओं की रोचक बातचीत और सामूहिक भावना देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से युवा छात्रों से बातचीत करते हैं। इस वर्ष, परीक्षार्थियों के साथ संवाद सत्र गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और दिल्ली में सात, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित किए गए।

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हमेशा की तरह, अपने युवा दोस्तों के साथ बातचीत करना और तनाव मुक्त परीक्षाओं एवं कई अन्य चीजों पर चर्चा करना ताजगी भरा होता है।''

मैंने कहा था वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, अब वो भारत के पक्ष में : पीएम मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर अब भारत के पक्ष में बदल रहा है, जो कोविड के बाद स्पष्ट हुआ है. पीएम मोदी ने धैर्य रखने पर जोर दिया और कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील से मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ेगी और देश में गुणवत्ता वाले उत्पाद बनेंगे. भारत और अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील के बाद हुई इस एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का फूल माला पहनाकर स्‍वागत किया गया. इस दौरान एनडीए सांसदों में गजब का जोश देखने को मिला. पीएम मोदी ने इस दौरान एनडीए के साथियों से कहा कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है. चुनाव हवा में नहीं जीता जाता है. चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छी नीति के साथ आगे ले जाना जरूरी है.

सेना और जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2-3 संदिग्ध जंगल में छिपे

(एजेंसी)।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में 3 फरवरी 2026 को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह घटना रामनगर क्षेत्र के जाफर जंगल में हुई, जहां खुफिया जानकारी के आधार पर 2-3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।

उधमपुर जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित जाफर जंगल इन दिनों सुर्खियों में है। यह इलाका काफी घना और दूरस्थ माना जाता है, जहां सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह इलाका वैसे भी संवेदनशील माना जाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए हैं।

यह ऑपरेशन सोमवार 2 फरवरी की सुबह शुरू हुआ था, जब सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की इनपुट मिली। शुरूआती सर्च ऑपरेशन के दौरान

मंगलवार 3 फरवरी को आतंकियों के साथ सीधी टक्कर हुई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, मुठभेड़ तेज होती चली गई और शाम तक गोलाबारी जारी रही।

इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और उफ्छक्र की संयुक्त टीम शामिल है। आतंकियों की घेराबंदी को मजबूत करने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ताकि जंगल के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। ग्राउंड फोर्सेस लगातार इलाके को कवर कर रही हैं और आतंकियों को भागने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। अब तक किसी भी आतंकी या सुरक्षाकर्मी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद (खीट)

जैश पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन है, जो पुलवामा हमले (2019) जैसी बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है। जम्मू क्षेत्र में हाल के महीनों में जैश के कई ऑपरेशन नाकाम किए गए हैं, जैसे जनवरी में कठुआ और अन्य इलाकों में एनकाउंटर। उधमपुर क्षेत्र में हाल ही में भी एनकाउंटर हुए हैं (जैसे दिसंबर 2025 में मजालता क्षेत्र में), जहां जैश के आतंकी सक्रिय थे। किश्तवाड़ में भी 3 जैश आतंकियों की तलाश जारी है, जो उधमपुर से सटा हुआ है।

NIA की श्रीनगर छापेमारी (मुनीर अहमद शाह NGO केस) के साथ ही यह ऑपरेशन घाटी और जम्मू दोनों में आतंकी नेटवर्क पर सख्ती दिखाता है। जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ और लोकल सपोर्ट नेटवर्क पर फोकस बढ़ा है।

एनकाउंटर पर सीएम योगी का जवाबः बोले- हमने भी पुलिस को पिस्तौल दी है...अगर मारे न तो क्या गोली खाएं?

(एजेंसी)।

लखनऊ। लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती जरूरी है। यूपी में निवेश बढ़ा है और कानून-व्यवस्था अब मजबूत हुई है।

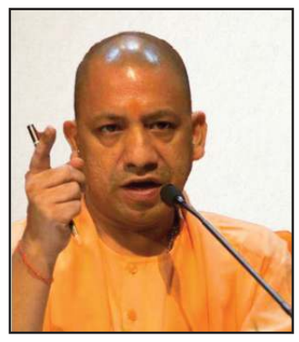

लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसमें सीएम योगी, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। इस दौरान सरकार ने 11 कंपनियों के साथ टङ्गव किया। इसके तहत मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर मिलकर शोध किया जाएगा। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा, जो माफिया और अपराधी के लिए है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली

न मारे तो क्या खाए?

सीएम योगी ने कहा, अगर कानून को कोई आंख दिखाता है तो उसको कानून अपने तरीके से अपने दायरे में लाकर अपने हिसाब से समझाता है। कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। एक वक्त यूपी के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज वो दूर की कौड़ी हो चुकी है।

यूपी को अब तक 50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

सीएम योगी ने कहा, यूपी को अब तक 50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेरोजगारी दर में यूपी सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आज हमारे पास लैंड बैंक भी है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे। हमने ललितपुर में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए लैंड अधिग्रहण की। पार्क के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में सेंटर लेवल की लैबोरेट्री पहले से मौजूद है।

राजस्थान के 21 हजार युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र जल्द, सीएम भजनलाल की घोषणा

(एजेंसी)। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन नीति-नियमों से होता है, चेहरे देखकर फैसले नहीं होते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के युवाओं के लिए एक खुशखबर दी। सीएम भजनलाल ने घोषणा की कि जल्द ही ही प्रदेश के 21 हजार युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र देंगे। प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का जल्द राजस्थान आने का कार्यक्रम बन रहा है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने चेहरा देखकर किए फैसले

सीएम भजनलाल ने कहा है कि सरकार नीति और नियमों के आधार पर काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती

कांग्रेस सरकारों ने चेहरा देखकर फैसले किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार में किसी भी प्रकार का निर्णय राजनीतिक दुर्भावना या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि तय मापदंडों के अनुसार लिया जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल सोमवार को दुगार्पुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में सरपंच संघ की ओर से आयोजित निवर्तमान सरपंच-प्रशासकों के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर संघ की ओर से सीएम का सम्मान भी किया गया।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1,500 की जनसंख्या पर बनाई गई पंचायत

पंचायत चुनावों और पंचायत गठन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि इसके लिए मापदंड तय हैं। सामान्य क्षेत्रों में 2,500 की आबादी पर पंचायत का गठन किया जा रहा है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1,500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई गई है।

लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म से नीचे गिरी बैट्री कार, मची अफरातफरी

लखनऊ। लखनऊ स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब यात्रियों को ले जाने वाली बैट्री ऑपरेटेड गोल्फ कार प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई, जिस

समय यह हादसा हुआ, उस समय कार में कोई यात्री नहीं बैठा था। कार चालक की लापरवाही सामने आने पर आरपीएफ ने उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरइंडिया और इंडिगो फ्लाइट के विंग्स आपस में टकराए, टला बड़ा हादसा

(एजेंसी)।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब एअर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के विंग्स जमीन पर आपस में टकरा गए। यह घटना तब हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे, हालांकि सभी सुरक्षित रहे।

एअर इंडिया की फ्लाइट अक 2732 मुंबई से कोयंबटूर के लिए रवाना होने से पहले पुशबैक प्रक्रिया में थी, जबकि हैदराबाद से मुंबई पहुँची इंडिगो की फ्लाइट 6ए 791 लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। इसी दौरान दोनों विमानों के विंगटिप आपस में टकराए।

एअर इंडिया ने आधिकारिक बयान में बताया कि फ्लाइट अक 2732 में देरी हुई क्योंकि उसका विमान टैक्सीवे पर खड़े दूसरे एयरलाइन के विमान से टकराया, जिससे एअर इंडिया के विमान के विंगटिप को नुकसान पहुँचा। एहतियातन विमान को तकनीकी जांच के लिए रोक दिया गया है।

राहुल बोले- अमेरिकी ट्रेड डील में पीएम पर प्रेशरःउन्होंने आपका खून-पसीना बेचा, पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने से रोका

नई दिल्ली , (एजेंसी)।

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में आपकी मेहनत के खून-पसीने को बेच दिया है। उन पर बहुत प्रेशर है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने से रोका गया।

इसके जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शाम को ट्रेड डील पर पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। कृषि-डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। इस डील पर दोनों देश जल्द साझा बयान जारी करेंगे।

दरअसल, ट्रम्प ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना अब बंद कर देगा।

राहुल ने कहा- एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ

राहुल ने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है। जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है।

ट्रम्प बोले- भारत हमसे 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा

ट्रम्प ने सोशल मीडिया 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट के जरिए ढट मोदी के साथ फोन पर बातचीत और भारत के साथ ट्रेड डील की जानकारी दी। उन्होंने लिखा- भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।

हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करना भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति जताई कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे और अमेरिका से कहीं ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'बाय अमेरिकन' को लेकर भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत भारत हमसे 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे।

ट्रम्प के पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- मुझे राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है।

इस शानदार फैसले के लिए मैं भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का दिल से धन्यवाद करता हूं।

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा) को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रम्प ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रेड डील की घोषणा की।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से कहा था कि दुनिया की पुरानी व्यवस्था 'टूट' रही है। अब मध्यम ताकत वाले देशों को साथ लाकर काम करना होगा। दावोस में अपने भाषण में कार्नी ने न तो ट्रम्प प्रशासन का नाम लिया और न ही उन अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया, जिनकी वजह से पुराना ग्लोबल सिस्टम हिल गया।

सम्पादकीय

कूटनीतिक कौशल के चलते यूएस डील

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह दावा कि भारत बिना वृषि और दुग्ध क्षेत्र के साथ बिना किसी समझौते के अमेरिका के साथ एक अच्छे टैरिफ करार पर सहमति बनी है। जबकि प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मंगलवार को ही राजग संसदीय दल की बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता एक बड़ा पैसला है जो हर देशवासी के लिए लाभदायक होगा। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी सरकार हमेशा राष्ट्र के हित में काम करती है।

दरअसल मोदी सरकार जिस तरह अमेरिका के साथ सौदेबाजी करने के लिए अपनी शर्तो पर अड़ी वह तो निति रूप से इस बात का परिचायक है कि सरकार ने भी धैर्य का परिचय दिया, भारत वंशियों ने भी धैर्य एवं संयम से काम लिया। भारतीय उत्पादकों को अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ में अतार्विक बढ़ोत्तरी के कारण बहुत नुकसान हुआ। किन्तु उन्हें इस बात का भरोसा था जब भी समझौता होगा तो अच्छा ही होगा। भारत सरकार अमेरिका स्थित भारतीय राजदूतावास और भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने जिस सक्रियता के साथ अमेरिकी प्राशासन के साथ समन्वय स्थापित किया और उन्हें हकीकत महसूस कराई, उसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्प दंडात्मक 25 प्रातिशत टैरिफ हटाया बल्कि 25 प्रातिशत से भी कम करके 18 प्रातिशत कर दिया जबकि भारत ने अमेरिका की शतरे को ठुकराकर रूस से तेल खरीदना बंद भी नहीं किया।

सच तो यह है कि भारत ने बजट में जिस तरह जीवन रक्षक दवाओं और चमड़ों पर आयात कर कम किया था, उसी का परिणाम है कि भारतीय ग्राहक और उत्पादक दोनों ही राहत महसूस करने लगे। साथ ही जिन देशों से दवाएं एवं जूते आदि आयात किए जाते हैं उन देशों के उत्पादकों ने भी राहत की सांस ली। सरकार ने तो बजट में इस बात की तैयारी कर ली थी कि वैसे टैरिफ आतंक की चुनौती से निपटा जा सकता है किन्तु लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने न सिर्प अमेरिका से वूटनीतिक रिश्ता कायम रखा बल्कि ट्रंप द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाए जाने के बाद न सिर्प रूस से फायदा लिया बल्कि चीन को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह भारत के साथ व्यापार संतुलन सुधारने के लिए भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाए। चीन ने भारत के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए न सिर्प अपने टैरिफ को कम किया बल्कि रेयर अर्थ मिनरल देने का भी वादा किया। रूस ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाते हुए व्यापारिक क्षेत्र को व्यापक बनाया। इसी वजह से भारत ने रूस से बहुत ज्यादा सोना खरीदा जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में न सिर्प स्थिरता और मजबूती आई बल्कि दुनिया के उन देशों और क्षेत्रीय संगठनों को नई दिल्ली की वूटनीति और व्यापार सहयोग की रणनीतिक सहभागिता विश्वसनीय प्रातीत हुई। इसी वजह से एफटीए की जो सौदेबाजी प्राव्रिया वर्षो से यूरोपीय यूनियन लटकाए पड़ा था, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए उतावला हो गया।

बहरहाल अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ का मुद्दा भले ही सुलझ गया किन्तु अब जो ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका एक तरफ वुआं दूसरी तरफ खाईं की होने वाली है, वह निति रूप से बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत हर बार की तरह इस बार भी ब्रिक्स मुद्रा में व्यापार की प्राव्रिया शुरू न करके वाशिगटन डीसी की बादशाहत कायम रखने में मदद करेगा जबकि भारत के साथ मिल कर चीन और रूस विश्व व्यापार में डालर की भूमिका को सीमित करना चाहते हैं। लब्बोलुआब यह है कि वूटनीति कौशल के साथ-साथ भारत ने अमेरिका को अपनी आर्थिक गुटबाजी के प्राभाव का भी एहसास कराया।

संसद में उपस्थिति, भागीदारी, बहस और जवाबदेही... तारीफ में पीएम मोदी के ये शब्द किस सांसद के लिए? बताया सीखने की मिसाल

संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है यह लोकतंत्र की आत्मा और आम जनता की शक्ति का केंद्र है. इसी आत्मा और आम लोगों के लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने वाला एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले दिया. एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे यह सीखना चाहिए कि संसद में परफॉर्मेंस कैसे की जाती है.

नई दिल्ली. (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दूबे की खुलकर तारीफ की. पीएम ने कहा कि निशिकांत दूबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद रहते हैं. हर महत्वपूर्ण डिस्कशन में भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ बहस करते हैं. यह मिसाल है कि संसद में कैसे प्रभावी योगदान दिया जा सकता है. सभी सांसदों को उनसे सीखना चाहिए. पीएम मोदी ने ये बातें 3 फरवरी 2026 की मीटिंग में कही जहां बजट सेशन और संसदीय कार्यों पर चर्चा हुई. जानकारों की नजर में पीएम मोदी की निशिकांत दुबे को लेकर की गई यह टिप्पणी केवल किसी एक सांसद की सराहना नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला संदेश है.

संसद में मौजूद रहना क्यों मायने रखता है

जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वह थी- संसद में सांसदों की उपस्थिति. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर अंत तक सदन में मौजूद रहते हैं. संसदीय लोकतंत्र में उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं होती. यह जनता के प्रति जवाबदेही का पहला कदम है. जिस सांसद ने जनता का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व लिया है, उनका सदन में रहना ही उसकी प्रतिबद्धता को बताता है. पीएम मोदी

का यह संदेश साफ है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद में खाली कुर्सियां नहीं सक्रिय जनप्रतिनिधि चाहिए.

बहस और भागीदारी से बनती है संसद की ताकत

पीएम मोदी के शब्दों को और गहराई से समझें तो निशिकांत दुबे की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि संसद की गरिमा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सार्थक बहस और विमर्श से बनती है. प्रधानमंत्री ने निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि वे हर महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेते हैं. बहस करना संसदीय अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है. जब सांसद चर्चा में भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और तर्क रखते हैं, तभी जन कल्याणकारी नीतियां बनती हैं और बेहतर परिणाम सामने आते हैं. पीएम मोदी का यह संदेश उन सांसदों के लिए भी है जो संसद को बहस का मंच नहीं केवल उपस्थिति रजिस्टर समझ लेते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित (अंडरलाइन) किया कि निशिकांत दुबे हर बहस से पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं. पीएम मोदी यह टिप्पणी मौजूदा राजनीति में बेहद अहम है. संसद में भावनात्मक भाषणों से ज्यादा तथ्य, आंकड़े और अध्ययन की जरूरत होती है. रिसर्च आधारित बहस न सिर्फ सरकार को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनाती है. पीएम मोदी का यह संदेश बताता है कि संसद में प्रभाव बनाने का रास्ता शोर नहीं बल्कि पुख्ता रिसर्च और स्पीच की तैयारी है.

पीएम मोदी की यह तारीफ जवाबदेही के व्यापक सिद्धांत से भी जुड़ी है. संसद में सवाल पूछना, नीतियों पर चर्चा करना और सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. जब सांसद सदन में सक्रिय रहते हैं, तब कार्यपालिका भी सतर्क रहती है. प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि संसद की मजबूती ही लोकतंत्र की मजबूती है, और यह मजबूती सांसदों की सक्रियता से आती है.

पार्टी के भीतर संदेश और राजनीतिक अर्थ

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो निशिकांत दुबे के लिए पीएम मोदी की यह तारीफ भाजपा और एनडीए के भीतर भी एक स्पष्ट संकेत है. पीएम मोदी यह बताना चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व सांसदों के व्यवहार, अनुशासन और संसदीय भूमिका को गंभीरता से देखता है. यह केवल लोकप्रियता की राजनीति नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी की राजनीति का संकेत है.

पीएम ने 'दिव्यांग' शब्द देकर बदली देश की सोच, दिव्यांगजनों को बताया राष्ट्र निर्माण के साझे सहभागी: सिंधिया

अशोकनगर/भोपाल, (एजेंसी)।

3 फरवरी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले के मरूप गांव में आयोजित भव्य 'दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सहायक उपकरण वितरण शिविर' में संवेदना और सम्मान के संकल्प को साकार किया।

इस अवसर पर उन्होंने 1237 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक सहायक उपकरण वितरित करते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ उपकरण वितरण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल में सेवा सिंधिया परिवार के लिए शासन का विषय नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से निभाया जा रहा एक पवित्र कर्तव्य रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशोकनगर में 1456, गुना में 1745 और शिवपुरी में 5250 सहित कुल पूरे संसदीय क्षेत्र में 8,240 दिव्यांगजनों तक सेवा पहुंचाने का लक्ष्य किसी आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 8,240 परिवारों की आशा, गरिमा और भविष्य से जुड़ा संकल्प है।

सिंधिया ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकलांग' के

स्थान पर 'दिव्यांग' शब्द देकर देश की सोच, संवेदना और दृष्टिकोण को नई दिशा दी है। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया जैसे उदाहरणों के माध्यम से कहा कि सामर्थ्य शरीर की सीमाओं से नहीं, बल्कि संकल्प और आत्मविश्वास से जन्म लेता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि दिव्यांगजन हमारे राष्ट्र निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी के सहभागी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों की विशेषता को पहचानते हुए देश के इतिहास में पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 संसद में पारित किया और दिव्यांगजनों के लिए आवंटन राशि को 330 करोड़ से 5 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ तक पहुंचाया। पूरे देश में पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा 18000 से अधिक शिविर लगाए गए हैं, जहां 21 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेल विभाग ने दिव्यांग ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र जारी किया है, जिससे दिव्यांगजनों को विशिष्ट रूप से टिकट मिलने की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 32 दिव्यांगजनों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह को भी इस पहल के लिए धन्यवाद किया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन के अंत में कहा, ह्लआपका यह सैनिक आपके सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके लिए लड़ेगा।ह्व उन्होंने सभी नागरिकों से 'विकसित भारत 2047' के संकल्प में सहभागी बनने और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में और सशक्त रूप से जोड़ने का आह्वान किया।

'प्रेग्नेंसी में सास ने पेट में लात मारी, मेरी खूब पिटाई की', करिश्मा कपूर का शॉकिंग खुलासा, छलका मेंटल दर्द

(एजेंसी)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दिवंगत पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर (२४ल्ल्रं८ डंस्र४१) की संपत्ति को लेकर अब एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर अधिकार को लेकर परिवार के अलग-अलग पक्ष आमने-सामने हैं। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, जहां इस हाई-प्रोफाइल केस में समन जारी किए गए हैं।

किन पक्षों के बीच है टकराव?

इस विवाद में मुख्य रूप से तीन पक्ष सामने आए हैं-

संजय कपूर की मां रानी सुरिंदर कपूर

संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव

करिश्मा कपूर से हुए संजय कपूर के दोनों बच्चे (बेटी समायरा और बेटा कियान)

रानी कपूर ने अदालत में दायर याचिका में कुल 22 लोगों के खिलाफ आरोप लगए हैं।

आरके फैमिली ट्रस्ट पर उठे सवाल

-याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के जरिए पारिवारिक संपत्ति को ट्रांसफर किया गया जिसकी जानकारी और सहमति रानी कपूर को नहीं दी गई थी। उनके अनुसार ये ट्रस्ट अवैध है और कानून के खिलाफ बनाकर संपत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। रानी कपूर ने अदालत से मांग की है कि इस ट्रस्ट को निरस्त किया जाए और संपत्ति के हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच हो।

-दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को समन जारी किए हैं। अब अदालत में दस्तावेजों, ट्रस्ट की वैधता और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कानूनी जांच होगी।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की दर्दनाक शादी

-इस मामले के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी भी फिर से सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें कि करिश्मा और संजय कपूर की शादी, तलाक और उससे जुड़े आरोप उस दौर में मीडिया की बड़ी खबरें बनी थीं।

-हाल के घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर वो पुराने आरोप चर्चा में हैं, जिनमें करिश्मा कपूर ने अपने पूर्व पति संजय कपूर और सास रानी कपूर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।

-ये सभी बातें उस समय करिश्मा कपूर द्वारा इंटरव्यू और कानूनी दस्तावेजों में किए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों पर दूसरी तरफ से अलग-अलग समय पर अपनी सफाई भी दी गई थी।

-करिश्मा कपूर ने अपने तलाक के दौरान दायर शिकायतों और इंटरव्यू में कहा था कि शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन वैसा नहीं रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। उनके मुताबिक उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा जाता था और छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था। करिश्मा कपूर ने दावा किया था कि घर का माहौल उनके लिए असहज और तनावपूर्ण हो गया था, जहां उन्हें सम्मान की बजाय ताने और दबाव झेलना पड़ता था।

धोनी ने बताया इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम का नाम, जीतने को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

(एजेंसी)।

क्रिकेट के गलियारों में आजकल टी20 वर्ल्ड कप की ही चर्चा है. यह टूनामेंट इसलिए खास है क्योंकि इसकी मेजबानी भारत खुद कर रहा है। लेकिन इस उत्साह के बीच 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी के एक हालिया वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। धोनी ने टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं पर ऐसी बात कही है जिसे हर क्रिकेट प्रेमी को जानना चाहिए।

जतिन सप्रू के साथ बातचीत के वायरल वीडियो में धोनी ने भारतीय टीम की ताकत का बारीकी से विश्लेषण किया है। धोनी का मानना है कि भारतीय पिचों पर टीम इंडिया को हराना किसी भी विदेशी टीम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। क्राउड

का सपोर्ट खिलाड़ियों में जो ऊर्जा भरता है, वह किसी टॉनिक से कम नहीं होता।

माही ने मौजूदा टीम के बेखौफ अंदाज की तारीफ की है। उन्होंने संकेत दिया कि आज के युवा खिलाड़ी नाम देखकर नहीं, बल्कि गेंद देखकर शॉट लगाते हैं, जो कि टी 20 जैसे छोटे फॉर्मेट की सबसे पहली जरूरत है।

धोनी ने जोर दिया कि टीम इंडिया में अब ऑलराउंडर्स और गहराई वाली बल्लेबाजी है, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से मैच निकाल सकती है। माही ने इस टीम को सबसे खतरनाक टीम बताया है।

धोनी के इस बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2026 के महाकुंभ में वह टीम इंडिया के साथ किसी नई भूमिका में नजर आएंगे? हालांकि धोनी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्रिकेट जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ टीम के बहुत काम आ सकती है।

भारतीय फैंस अभी भी 2007 की उस जीत को नहीं भूले हैं जब धोनी की कप्तानी में भारत पहला टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब करीब दो दशक बाद, जब टूनामेंट फिर से दहलीज पर है, तो धोनी के शब्द फैंस के लिए किसी गारंटी से कम नहीं लग रहे।

3 भारतीय खिलाड़ी बेंच पर बैठे रह जाएंगे, टी 20 वर्ल्ड कप इलेवन में मौका मिलना लगभग नामुमकिन

(एजेंसी)।

टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूनामेंट में प्लेइंग इलेवन का चुनाव सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि फॉर्म, कॉम्बिनेशन और रोल क्लैरिटी पर होता है। भारतीय टीम इस बार बेहद संतुलित नजर आ रही है, लेकिन इसी संतुलन की वजह से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पूरे टूनामेंट के दौरान बेंच पर बैठकर ही टीम का सफर देखना पड़ सकता है।

हम बात कर रहे हैं उन तीन खिलाड़ियों की, जिनका नाम स्क्वॉड में तो है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना बेहद मुश्किल दिख रहा है। उन तीन प्लेयर्स के बारे में आपको भी जानना चाहिए, इससे टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा।

1. संजू सैमसन

संजू सैमसन का नाम आते ही फैंस को उम्मीद बंधती है, लेकिन हालिया फॉर्म ने उनकी दावेदारी को कमजोर कर दिया है। टी20 फॉर्मेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन न कर पाना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या

बन गया है।

टीम मैनेजमेंट की प्राथमिकता साफ है कि विकेटकीपिंग में ईशान किशन पहले विकल्प होंगे। ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी, पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता और हालिया निरंतरता उन्हें संजू से आगे रखती है। ऐसे में संजू सैमसन के लिए प्लेइंग इलेवन का दरवाजा लगभग बंद नजर आता है और उनके लिए यह वर्ल्ड कप बेंच पर बैठकर ही गुजर सकता है।

2. हर्षित राणा

हर्षित राणा ने घरेलू क्रिकेट और क्कछ में अपनी तेज गेंदबाजी से जरूर प्रभावित किया है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जैसे मंच पर टीम संयोजन ज्यादा अहम हो जाता है। भारतीय टीम में पहले से ही हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का संतुलन देते हैं। ऐसे में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को मौका मिलना बेहद कठिन है। टीम जरूरत के हिसाब से ऑलराउंड ऑप्शन को तरजीह देगी, जिससे हर्षित का रोल बैकअप तक ही सीमित रह सकता है।

3. वाशिंगटन सुंदर : वाशिंगटन सुंदर का मामला सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। टीम में पहले से अक्षर पटेल मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी तीनों में ज्यादा प्रभावी विकल्प माने जा रहे हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे प्रॉपर विकेट-टेकिंग स्पिनर टीम की पहली पसंद हैं। ऐसे में सुंदर की उपयोगिता सीमित हो जाती है। परिस्थितियां बेहद खास न हों, तो उनके लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना लगभग असंभव नजर आता है।

सोना-चांदी 40,000 रुपये तक महंगा!आम आदमी की बढ़ी मुसीबत, जानिए अचानक क्यों लौटी तेजी?

(एजेंसी)।

पिछले पांच दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में ऐसी तेज गिरावट देखी गई कि निवेशकों के हाथ-पांव फूल गए। चांदी जहां अपने रिकॉर्ड हाई 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से फिसलकर करीब 2 लाख रुपये की गिरावट की ओर बढ़ गई थी, वहीं सोना भी 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से टूटकर करीब 1.43 लाख रुपये तक आ गया था।

लगातार तीन सत्रों की भारी बिकवाली ने बाजार का मूड पूरी तरह नेगेटिव कर दिया था। लेकिन 3 फरवरी 2026 को तस्वीर अचानक बदल गई। वायदा बाजार में सोने और चांदी ने जोरदार वापसी की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 मार्च 2026 डिलिवरी वाली चांदी में शाम करीब 7 बजे जबरदस्त तेजी दिखी। कीमत एक झटके में 40,000 रुपये से ज्यादा उछल गई।

खबर लिखे जाने तक चांदी 2,74,558 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। दिन का हाई 2,78,000 रुपये और लो लेवल 2,45,711 रुपये रहा। इससे पहले चांदी 2,36,261 रुपये पर बंद हुई थी।

सोने की बात करें तो अप्रैल डिलिवरी वाला सोना 7,923 रुपये यानी करीब 5.5 प्रतिशत उछलकर 1,51,914 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले तीन सत्रों में सोना लगभग 40,000 रुपये या 22 प्रतिशत तक टूट चुका था।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में भी सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार रिकवरी देखी गई। चांदी 24,000 रुपये की छलांग लगाकर 2.84 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई। वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 5,000 रुपये बढ़कर 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस उछाल के पीछे तीन बड़े कारण हैं।

पहला, भारी गिरावट के बाद सोना-चांदी सस्ते स्तर पर पहुंचे, जिससे निवेशकों ने जमकर खरीदारी की।

दूसरा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिला।

तीसरा, अमेरिका में बढ़ते राजकोषीय जोखिम और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर उठते सवालों के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग फिर से बढ़ी है।

आगे क्या रहेगा ट्रेंड?

जानकारों का मानना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन गिरावट के बाद आई यह तेजी बताती है कि सोना-चांदी अभी भी निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

निर्मला सीतारमण ने की घोषणा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लपक लिया मौका

उत्तर प्रदेश अब फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख हब बनाने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया. इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ दिग्गज निवेशकों का जमघट लगने वाला है.

लखनऊ. (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की. इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे जैविक दवाओं, बायोसिमिलर्स और संबंधित क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इस केंद्रीय घोषणा ने उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा भर दी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लपकते हुए राज्य को फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख हब बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है.

इसी कड़ी में आज मंगलवार को लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल ताज में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0: इन्वेस्ट मोंट अपॉर्च्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश का आयोजन हो रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथस्वयं करेंगे. कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और इन्वेस्ट यूपी संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं रसायन-उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे. कॉन्क्लेव में देश-विदेश की प्रमुख फार्मा कंपनियों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें दिलीप सांघवी (चेयरमैन, सन फार्मा), पंकज आर. पटेल (चेयरमैन, जाइडस फार्मा), रमेश जुनेजा (चेयरमैन, मैनकाइंड फार्मा), डॉ. सतीश रेड्डी (चेयरमैन, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज), जीनल मेहता (वाइस चेयरमैन, टोरेंट फार्मा) और अयोध्या रामी रेड्डी (चेयरमैन, रामकी ग्रुप) आदि शामिल हैं.

ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर बड़ा कदम

ये उद्योगपति निवेश, उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेंगे. एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जिसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को रीढ़ की हड्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है. राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल उपभोक्ता बाजार इसे आकर्षक बनाते हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है. बायोफार्मा फंड से भारत ग्लोबल हब बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले से तैयार है. फार्मा कॉन्क्लेव से नए निवेश, साझेदारियां और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च-स्तरीय नौकरियां मिलेंगी. यह आयोजन उत्तर प्रदेश को फार्मा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जहां केंद्रीय बजट की घोषणा और राज्य सरकार की सक्रियता मिलकर देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाएंगी.

मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर जोरदार तरीके से गूंजा

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन

नई दिल्ली,

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर जोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत यह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की जरूरत है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने भाषा संरक्षण में परिवारों, विशेष रूप से माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डोगरों से एकजुट, प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को बधाई भी दी।

लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत ह्माये निं मेरिये, जम्मूऐ दी राहे, चंबा कितनी क दूरह्व में कथित छेड़छाड़ के विरोध में प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा ने गीत को उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज उठाने वाले हिमाचली कलाकारों की सराहना की।

वरिष्ठ पत्रकार और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने का प्रयास है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लस्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्राफियां भेंट कर के सम्मानित किया।

कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा , कुलवीर सिंह , कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगी हुई है।

22वीं किस्त से पहले बदल गया पीएम किसान का नियम, नहीं बनवाई ये आईडी तो रुक जाएंगे पैसे

(एजेंसी)।

मध्य प्रदेश सहित देशभर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। योजना की 21 सफल किस्तों के बाद, अब 22वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है।

सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे डीबीटी (ऊइळ) के माध्यम से खातों में पहुंचती है। हालांकि, इस बार सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फजीर्वाड़े को रोकने के लिए 'फार्मर आईडी' (ऋंील्ल कऊ) को अनिवार्य कर दिया है।

यह डिजिटल पहचान पत्र अब अगली किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अगर आप भी फरवरी में आने वाली अगली किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के उठाना चाहते हैं, तो नई गाइडलाइंस को समझना आपके लिए अनिवार्य है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। सरकारी नियमों के अनुसार, हर चार महीने के अंतराल पर किस्त जारी की जाती है। इस आधार पर 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारी अंतिम चरण में है।

क्यों अनिवार्य हुई फार्मर आईडी?

सरकार अब किसानों के डेटा को पूरी तरह डिजिटल कर रही है। फार्मर आईडी बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसान के आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है। इससे:

पात्र किसानों की सटीक पहचान हो सकेगी।

बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगेगी।

भविष्य की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिलेगा।

नोटः जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी अपडेट नहीं की है, उनकी फरवरी वाली किस्त रोकी जा सकती है।

फार्मर आईडी बनवाने के 3 आसान तरीके

किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने इसे बेहद सरल बनाया है। आप नीचे दिए गए तरीकों से अपनी आईडी बनवा सकते हैं:

ऑनलाइन पोर्टलः किसान स्वयं आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

उरउ सेंटरः अपने नजदीकी 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) पर जाकर मामूली शुल्क के साथ इसे बनवाया जा सकता है।

ग्राम पंचायत कैंपः कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर (CÔmps) लगाए जा रहे हैं, जहां कर्मचारी मौके पर ही किसानों की मदद कर रहे हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आईडी बनवाने के लिए किसान भाई इन दस्तावेजों को अपने पास जरूर रखेंः

आधार कार्डः पहचान के प्रमाण के लिए।

भूमि दस्तावेजः जमीन की खतौनी या खसरा की कॉपी।

मोबाइल नंबरः आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

अगली किस्त आने में अब बहुत कम समय बचा है। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है या अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो तुरंत इस काम को प्राथमिकता दें। यह न केवल पीएम किसान की 22वीं किस्त सुनिश्चित करेगा, बल्कि कृषि से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं के द्वार भी आपके लिए खोल देगा।

नर्मदा में राजनीतिक भूचाल, भाजपा-कांग्रेस के 1000 से ज्यादा लोग आप में शामिल हुए

अहमदाबाद/नर्मदा/भरूच/

जिले के चीकदा गांव में अअढ की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें अअढ विधायक चैतर वसावा, दिल्ली से आए विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। विधायक और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के 1000 से भी ज्यादा लोग अअढ में शामिल हुए थे। साथ ही साथ इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और अअढ को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार वर्षों से केवल कागजों पर ही रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निश्चित रूप से जमीन पर लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही आदिवासी समाज की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वन अधिकार कानून के तहत जिन लोगों के अधिकार लंबित हैं, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 505 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जाएगा। इसके अलावा 181 गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां स्कूल शुरू किए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। जिले में 1200 से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसे दूर करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी और बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के प्रयास किए जाएंगे।

युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासी युवा पुलिस, कअर, क्ढर, डॉक्टर और शिक्षक बनें, इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार चिंतित और प्रयासरत है। लेकिन भाजपा सरकार की तानाशाही और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण आदिवासी समाज को उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास की ग्रांट का उपयोग अपने प्रचार और कार्यक्रमों के लिए करती है। आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में सत्ता प्राप्त किए बिना आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। उन्होंने 2027 में पूरे गुजरात में परिवर्तन लाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सांसद मनसुख वसावा पर निशाना साधते हुए आप नेता चैतर वसावा ने सार्वजनिक चर्चा और डिबेट के लिए तैयारी जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई बार आदिवासी समाज के मुद्दे उठाए हैं, जबकि भाजपा सांसद ने लोकसभा में आदिवासी समाज के लिए क्या किया है, यह जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए।

विधायक चैतर वसावा ने आगे कहा कि डेडियापाड़ा की जनता की एकता और शक्ति ऐसी है कि आज देश के प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी डेडियापाड़ा आना पड़ता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस सहित अन्य दलों के दिग्गज नेता भी डेडियापाड़ा आएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। इस मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश-विदेश से कोई भी नेता आए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों में जागरूकता फैलाने, लोगों को एकजुट करने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो, सड़क हो या मैदान—जहां भी जरूरत पड़े, वे जनता की आवाज उठाते हैं, जो भाजपा सरकार को पसंद नहीं है। भाजपा के कुछ नेता और उनके समर्थक लोगों पर दबाव डालने के लिए फोन करते हैं और लोगों को डेडियापाड़ा न आने देने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह शक्ति और हिम्मत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे साथ सरपंच, जिला प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग तथा माता-पिता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसी जनसमर्थन के कारण मैं इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मनरेगा सहित विभिन्न मुद्दों पर नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती—ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक वन अधिकारों पर स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज इस जंगल में आदिकाल से निवास करता आया है और लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज पर उनका अधिकार है। इस मुद्दे पर वन विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों पर अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरेंगे।

आम आदमी पार्टी गुजरात

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जिला कलेक्टरों से आह्वान- आगामी मानसून से पहले ही जल संचय के कार्यों का अग्रिम आयोजन कर बरसाती पानी के अधिकाधिक संचय और संग्रह के जरिए जल संचय के क्षेत्र में गुजरात का नेतृत्व बनाए रखें

गांधीनगर, 03 फरवरी : राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वग्राही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई।

इस समीक्षा बैठक में दिल्ली से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांताराव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ गांधीनगर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और वरिष्ठ सचिव शामिल हुए।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के बनासकांठा, कच्छ और राजकोट जिले के कलेक्टरों के प्रेजेंटेशन सहित विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान की प्रगति और आगामी आयोजन की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान देने का मार्गदर्शन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए 'कैच द रेन' अभियान और जल संचय की राष्ट्रव्यापी मुहिम का अधिक से अधिक लाभ गुजरात को मिले।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को सीख देते हुए कहा कि वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिलों में बरसाती पानी के संग्रहण और संचयन के कार्य करें। ये सभी ऐसे जनहित के कार्य हैं, जिनसे कर्तव्य निभाने के कार्य संतोष के साथ-साथ आत्मसंतोष भी मिलता है।

मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण बनाने की हिमायत की जिसमें राज्य के जिलों के बीच जल संचय-जनभागीदारी अभियान के कार्यों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और जिन जिलों में जल संचय का काम कम हुआ हो, उन्हें भी अधिक कार्य करने का बल मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया है, इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि इसका भी उपयोग जिलों में जल संचय के कार्यों के लिए हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जल संचय के व्यापक कार्यों को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य को आवंटित 553 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का संपूर्ण उपयोग मार्च-2026 से पहले हो जाए।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जल संचय-जल संग्रह क्षेत्र में गुजरात ने जो कार्य किया है, वह देश में मॉडल बन गया है।

उन्होंने कहा कि पुराने बोर रिचार्ज करने की 70 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा देने के निर्णय से बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने जल संचय के कार्यों में अधिक संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जोड़ने के लिए एक सूची बनाकर उन्हें प्रेरित करने पर जोर दिया।

श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लागू होने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत मिलने वाले फंड का 40 फीसदी जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसा उदार प्रावधान किया गया है।

उन्होंने इस योजना के अंतर्गत समय पर और योजनाबद्ध तरीके से धन खर्च करने का मार्गदर्शन देते हुए कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से वाटर स्ट्रक्चर बनाकर जल संचय-जल संग्रह क्षमता में निरंतर वृद्धि से प्रधानमंत्री के जल सुरक्षा-जल आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरा हो सकेगा।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चालू वर्ष में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के तहत आगामी 31 मई, 2026 तक देश भर में एक करोड़ से अधिक जल संग्राहक स्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए गुजरात में जल संचय के अधिकतम कार्य अगले मानसून से पहले पूर्ण करने का सुझाव दिया।

बैठक में इसकी भी समीक्षा की गई कि जल संचय जन भागीदारी 01 अभियान के तहत गुजरात में कुल 1,33,522 जल संचय के कार्य पूरे किए गए हैं तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ट्यूबवेल, तालाब गहरा करने, खेत तालाब और फिल्टर वेल जैसे जल संचय के कार्य होने से भूगर्भ जल रिचार्ज में बड़ा फायदा हुआ है।

दिल्ली में हर दिन 27 लोग लापता,मेट्रो पर बड़ा अपडेट,

(एजेंसी)।

दिल्ली में आज 4 फरवरी को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आप एक नजर में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। राजधानी से जुड़ी अपराध, मेट्रो, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्ट से आई उन खबरों को हम आसान भाषा में समझा रहे हैं, जो सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं।

साल 2026 की शुरूआत के साथ ही दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार जनवरी के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए। इनमें से 235 को खोज लिया गया, लेकिन 572 लोग अब भी लापता हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है।

लापता बच्चों में 137 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें 120 लड़कियां हैं। यानी सबसे ज्यादा किशोरियां गायब हो रही हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 12 से 18 साल के बच्चों के मामले सबसे अधिक हैं। सिर्फ इसी आयु वर्ग में 169 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 121 अब तक नहीं मिले। यह आंकड़े दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के पूरा होते ही राजधानी और आसपास के शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। इस फेज में 6 नए कॉरिडोर और 84 नए स्टेशन जुड़ेंगे। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन जैसे हिस्सों में ट्रायल रन शुरू हो चुका है।

फेज-4 पूरा होने पर इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो जाएगी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली के किसी भी कोने तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक सभी लाइनें चालू हो जाएं।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी रक्क्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर विचार किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर सुनवाई करेगी। संभावना जताई जा रही है कि ममता बनर्जी खुद अदालत में मौजूद रह सकती हैं। यह मामला सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर अहम माना जा रहा है।

दिल्ली में ट्रैफिक से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि राजधानी में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

वसंत कुंज से शिव मूर्ति तक 5 किमी लंबी टनल बनाई जाएगी। अक्क्टर से महिपालपुर तक एलिवेटेड रोड बनेगी। कालिंदी कुंज इंटरचेंज, पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर रोड, मथुरा रोड और महरौली-गुड़गांव रोड के विकास पर भी बड़े पैमाने पर काम होगा। इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सजा को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने साफ कहा कि बार-बार समय मांगने और भुगतान न करने का रवैया स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले उनकी सजा निलंबित की गई थी, लेकिन शर्तें पूरी न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

लापता बच्चों से लेकर मेट्रो विस्तार, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स और हाईकोर्ट के सख्त आदेश तक - दिल्ली आज हर मोर्चे पर सुर्खियों में है। अगर आप राजधानी की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट्स आपको पूरे हालात एक साथ समझने में मदद करती हैं।

'यूपी फार्मा कॉन्क्लेव' में सीएम योगी बोले- भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा...

(एजेंसी)।

'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आभारी हैं, जिन्होंने रोलबैक करते हुए भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अपनी नीतियों पर अडिग था, और इसका परिणाम है 'सत्यमेव जयते'। यह पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकसित भारत और बढ़ते भारत की यात्रा का प्रमाण है, जहां भारत एक जिम्मेदार और भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगाह भी किया कि भारत की इस बढ़ती ताकत से कुछ लोग सशंकित भी हैं, इसलिए देश को विश्वसनीय सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते हुए सतर्कता और विवेक के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जिस भारत को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, आज वही भारत अपनी नीतियों पर दृढ़ रहते हुए वैश्विक शक्तियों को भी संवाद और सहयोग के लिए विवश कर रहा है।

भारत अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है और स्वयं अपना नियंता बन रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि आज देश वैश्विक चुनौतियों और दबावों के बीच आत्मविश्वास, नीति-

स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है।

'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जब हम लोग सत्ता में आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जमीन ढूंढते हुए नहीं बनती थी। कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू-माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा, 24 घंटे का समय दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर जिस भू माफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दे। 24 घंटे के बाद जब हम कारवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ-साथ उसने जो कमाई की होगी, उसकी ब्याज सहित वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी 65000 एकड़ लैंड खाली हुई थी। यह हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए।

'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' के दौरान राज्य के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर सहमति बनी है, जिसमें औषधि, चिकित्सा उपकरण एवं संबंधित क्षेत्रों में 5,525 करोड़ रुपये के 11 एमओयू का आज मंच पर औपचारिक आदान-प्रदान किया गया।

प्रमुख निवेशकों में अर्ना फार्मा व बायोजेंटा लाइफ साइंसेज ने 1,250-1,250 करोड़ रुपये, शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स ने 737 करोड़, वाल्टर बुशनेल एंटरप्राइज ने 590 करोड़, ज्ञानविका लैब्स ने 553 करोड़, कोरो हेल्थ ने 418 करोड़, मार्क लेबोरेटरीज ने 300 करोड़, हाई ग्लांस लैबोरेटरीज ने 120 करोड़, रासपा फार्मा ने 107 करोड़, रोमसंस मेडवर्ल्ड ने 100 करोड़ और कोटक हेल्थकेयर ने 100 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जिससे उत्तर प्रदेश के फार्मा निवेश के नए केंद्र के रूप में उभरने को मजबूती मिली है।

क्या अन्नामलाई विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ रहे?

(एजेंसी)।

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तमिलनाडु के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के बारे में चर्चा में हैं कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका यह कदम व्यक्तिगत कारणों से है, न कि भाजपा छोड़ने का इरादा।

अन्नामई ने साफ किया है कि फिलहाल वे व्यक्तिगत कारणों के चलते चुनावी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं, न कि भाजपा छोड़ने के इरादे से। उनके पिता की सेहत की देखभाल को उन्होंने "पहला कर्तव्य" बताया है।

बताई वजह

अन्नामलाई ने कोयंबटूर में मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके पिता अस्वस्थ हैं और उनकी देखभाल करना उनका "पहला कर्तव्य" है। इसके चलते वह चुनावी जिम्मेदारियों और पार्टी के बुनियादी कामों में सक्रिय नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं प्रचार या मुझे सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हूं।"

सौंपी गई ये अहम जिम्मेदारी

अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने उनके निर्णय को स्वीकार लिया है। सिंगनल्लूर, मदुरै दक्षिण, विरुगम्बक्कम, कराईकुडी, श्रीवैकुंटम और पद्मनाभपुरम की जिम्मेदारियां अब अन्य नेताओं को सौंपी जाएंगी। भाजपा छोड़ने की अफवाहों के बीच उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं प्रचार करने या मुझे सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हूं।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा?

सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई भाजपा आलाकमान से नाखुश हैं, पर अलग पार्टी बनाने का कोई संकेत नहीं। तमिलनाडु में लोकप्रिय चेहरा बनने के बाद, अन्नामलाई ने पहले भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को सुचारु बनाने हेतु प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तभी से अटकलें हैं कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है या वह नई पार्टी बना सकते हैं।

अक्टूबर 2025 में, ऐसी अटकलों पर उन्होंने कहा था कि राजनीति स्वैच्छिक है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह में विश्वास जताते हुए भाजपा में शामिल होने की बात कही, मानते हुए कि वे तमिलनाडु में "शुद्ध राजनीति" लाएंगे।

अल्लल्लें' तमिलनाडु भाजपा के लिए क्यों हैं जरूरी?

एक किसान परिवार से आने वाले पहली पीढ़ी के राजनेता के तौर पर, उन्होंने बिना राजनीतिक समर्थन के नई पार्टी का विचार खारिज किया। अपनी सीमाओं के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने पार्टी की मांगों से अंतरात्मा के खिलाफ बोलने की बात मानी, पर आशा जताई कि "अच्छी चीजें होंगी।"

हालांकि, उनके पार्टी छोड़ने की अफवाहें जारी हैं, फिर भी उनके बयान बताते हैं कि वे व्यक्तिगत और राजनीतिक जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए फिलहाल भाजपा के दायरे में बने हुए हैं।

अन्नामलाई प्रोफाइल

पूरा नामः के. अन्नामलाई

पदः पूर्व भाजपा तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष

राजनीतिक करियर

किसान परिवार से आने वाले पहली पीढ़ी के नेता

तमिलनाडु में भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को मजबूत करने में अहम भूमिका

राष्ट्रीय नेतृत्व (मोदी, शाह) में भरोसा

हालिया स्थिति (2026 विधानसभा चुनाव):

चुनावी जिम्मेदारियों से फिलहाल हटे, कारणः पिता की देखभाल

पार्टी ने उनके निर्णय को स्वीकार किया

सिंगनल्लूर, मदुरै दक्षिण, विरुगम्बक्कम, कराईकुडी, श्रीवैकुंटम और पद्मनाभपुरम की जिम्मेदारियां अन्य नेताओं को दी गईं

खासियत

पहली पीढ़ी के नेता होने के बावजूद तमिलनाडु में लोकप्रिय चेहरा

व्यक्तिगत जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं

पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा

क्या इस साल बढ़ेगी आपके बच्चे के स्कूल की फीस? सरकार के इस फैसले ने बदल दी पूरी तस्वीर

(एजेंसी)।

दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों की फीस को लेकर चल रही लंबी खींचतान के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला नया रेगुलेशन कानून अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। पहले इसे 2025-26 से लागू करने की योजना थी, लेकिन कानूनी बारीकियों और सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार ने इसे एक साल के लिए टालने का निर्णय लिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी इस नई समयसीमा की जानकारी साझा की। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बदलाव के बावजूद, मौजूदा सत्र 2025-26 में स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे पैरेंट्स की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ फिलहाल टल गया है।

2025-26 सत्र में पुरानी फीस पर ही चलेगा काम

सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दिया है कि इस साल किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस में वृद्धि करने की इजाजत नहीं है।

स्कूल केवल वही फीस ले सकेंगे जो 1 अप्रैल 2025 तक लागू थी।

यदि किसी स्कूल ने इस बीच फीस बढ़ा दी है, तो उसकी कड़ी जांच की जाएगी।

अदालती फैसलों के आधार पर बढ़ी हुई राशि अभिभावकों को लौटानी या भविष्य की फीस में एडजस्ट करनी पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बदला फैसला

पिछले महीने कई निजी स्कूलों ने इस कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में कई स्कूलों की फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन कानून को लागू करने में जल्दबाजी न दिखाई जाए। इसी सलाह को मानते हुए सरकार ने कानून की समयसीमा को आगे बढ़ाया है ताकि कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन

नए कानून के तहत हर स्कूल में एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए एक सख्त टाइमलाइन जारी की है:

10 दिन के भीतरः हर प्राइवेट स्कूल को अनिवार्य रूप से रछत्र्स्क्ष्ठ का गठन करना होगा।

14 दिन के भीतरः कमेटी बनने के बाद स्कूल को अगले तीन सत्रों (2026-27 से 2028-29) के लिए प्रस्तावित फीस का विवरण देना होगा।

30 दिन के भीतरः जिला स्तर पर 'अपील कमेटी' बनाई जाएगी, जहां माता-पिता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

फीस साइकिल और पारदर्शिता के नए नियम

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फीस साइकिल (3 साल) के बीच में कोई भी स्कूल अचानक रकम नहीं बढ़ा सकेगा। जब तक नई फीस तय नहीं हो जाती, स्कूल पुरानी दर से ही पैसे लेंगे। यदि कोई अतिरिक्त राशि ली जाती है, तो उसे बाद में तय की गई फीस में समायोजित करना अनिवार्य होगा।

देवरिया ने लखनऊ को 71 रन से हराया

(एजेंसी)।

नौतनवा। नगर स्थित इंटर कॉलेज खेल मैदान में जारी मां सावित्री मणि त्रिपाठी मेमोरियल अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 4 में मंगलवार को क्रिकेट एकेडमी देवरिया एवं अजुर्ना क्रिकेट एकेडमी लखनऊ के बीच मैच खेला गया। देवरिया की टीम ने लखनऊ के खिलाड़ियों को पराजित कर दिया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि समाज सेवी गौरव तिवारी ने खेल का शुभारंभ किया।

मैच के दौरान देवरिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए।

देवरिया की तरफ से शेखर सहानी ने सर्वाधिक 65 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की पूरी टीम 18 ओवर में मात्र 73 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लखनऊ की तरफ से वारिश अली ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। शेखर सहानी मैन ऑफ द मैच चुने गए। कोच करीम खान के देखरेख में मैच हुआ। एम्पायर की भूमिका सरवन यादव और प्रिन्स सहानी एवं स्कोरर व कमेंट्री की भूमिका बृजेश सहानी, कार्तिक सहानी, सूर्यदेव यादव, आसिफ सिद्दिकी व अभिजीत भारती ने निभाई।

सदन में पेपर उछालने वाले 8 निलंबित सांसद कौन हैं? किस पर कितने केस?

(एजेंसी)।

संसद के बजट सत्र के पांचवें दिन 3 फरवरी 2026 को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड (अप्रकाशित) संस्मरण (मेमॉयर) का हवाला देते हुए 2020 के लद्दाख बॉर्डर टेंशन पर बात उठाई, जिससे सत्ताधारी इखढ और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। स्पीकर ने अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र करने पर रोक लगाई, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज के टुकड़े उछाले।

इस अनुशासनहीनता पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (ङ्क्षील्ल फ्र४) ने प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 8 विपक्षी (मुख्य रूप से कांग्रेस) सांसदों को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया। ये निलंबन 'अनुशासनहीन व्यवहार' और सदन में कागज फेंकने के लिए किया गया। आइए जानते हैं इन 8 निलंबित सांसदों की कुंडली खंगालने हैं किस पर कितने क्रिमिनल केस? निलंबित 8 सांसदों की पूरी लिस्ट (कांग्रेस से ज्यादातर)

1.अमरिंदर सिंह राजा वडिंग

क्षेत्रः पंजाब से (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 0 (कोई क्रिमिनल केस नहीं)

अन्य डिटेलः संपत्ति 17 करोड़ से ज्यादा, देनदारियां 4 करोड़ से ज्यादा। शिक्षाः मैट्रिक (1995)।

2. डॉ. प्रशांत यदोराव पाडोले

क्षेत्रः महाराष्ट्र से (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 0

अन्य डिटेलः संपत्ति 14 करोड़ से ज्यादा, देनदारियां 2 करोड़ से ज्यादा। शिक्षाः MD (मेडिकल) यूक्रेन से (2002)।

3. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

क्षेत्रः इडुक्की, केरल (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 88 (कई पुराने केस, मुख्य रूप से राजनीतिक या अन्य)

अन्य डिटेलः संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा, देनदारियां 36 लाख से ज्यादा। शिक्षाः स्नातकोत्तर (एमए राजनीति, एलएलबी)।

4. मणिकम टैगोर

क्षेत्रः विरुधुनगर, तमिलनाडु से (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 1

अन्य डिटेलः संपत्ति 6 करोड़ से ज्यादा, देनदारियां 95 लाख से ज्यादा। शिक्षाः एलएलबी (1998, बैंगलोर यूनिवर्सिटी)।

5. हिबी ईडन

क्षेत्रः एनार्कुलम, केरल (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 10

अन्य डिटेलः संपत्ति म्३ करोड़+, देनदारियां ~44 लाख+। शिक्षाः बीकॉम (2003-04, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी)।

6. गुरजीत सिंह औजला

क्षेत्रः अमृतसर, पंजाब (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः 10

अन्य डिटेलः संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा, देनदारियां 1.37 करोड़ से ज्यादा। शिक्षाः बीए (1992, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी)।

7. किरण कुमार रेड्डी

क्षेत्रः आंध्र प्रदेश (कांग्रेस)

आपराधिक मामलेः उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं (ज्यादातर मामलों में 0-कम)

अन्य डिटेलः पूर्व मुख्यमंत्री रहे, संपत्ति और शिक्षा की डिटेल अलग-अलग स्रोतों से चेक करें।

8. एस वेंकटरमन

क्षेत्रः मदुरै (तमिलनाडु)

पार्टीः (CPM) सांसद

आपराधिक मामलेः 3

संपत्तिः ₹2,05,36,639 -2 करोड़+

शिक्षाः 12वीं पास

अन्य डिटेलः संपत्ति और अन्य जानकारी सीमित।

क्या है पूरा माजरा?

आपको बता दें कि, 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने नरवणे की अप्रकाशित किताब से 31 अगस्त 2020 को 4 चीनी टैंक बॉर्डर पर पहुंचने का जिक्र किया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्तिजनक बताया। स्पीकर ओम बिरला ने अनपब्लिश्ड मटेरियल पर रोक लगाई, लेकिन विपक्ष नहीं माना। वहीं, इसका असर संसद के बजट सत्र के पांचवें दिन में भी नजर आया। कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज के टुकड़े उछाले। ऐसे में 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

निलंबन का क्या अर्थ?

दरअसल, लोकसभा नियमों के तहत स्पीकर कुर्सी की अवमानना, नारेबाजी और कागज फेंकना अनुशासनहीनता माना जाता है। किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पास किया। ये 8 सांसद सत्र के बाकी दिनों तक सदन में नहीं बैठ सकते, वोट नहीं दे सकते। कांग्रेस ने इसे 'तानाशाही' बताया, जबकि इखढ ने 'सदन की मयार्दा बचाने' का दावा किया।

युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री!

(एजेंसी)।

मणिपुर की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। मणिपुर लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। ये मैतेई नेता है।

युमनाम खेमचंद सिंह कौन हैं

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। खेमचंद सिंह दो बार के विधायक हैं और पिछली एन. बीरेन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वे मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद जातीय हिंसा के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

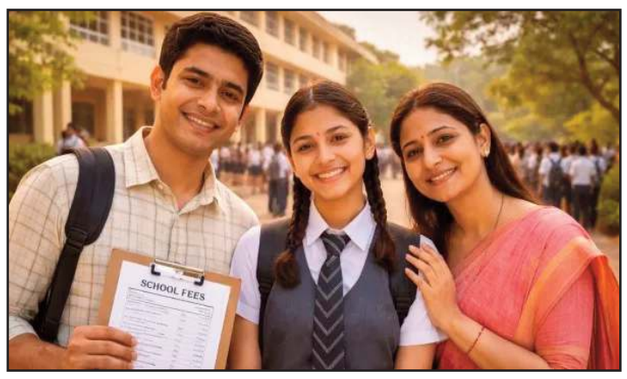

मौजूदा राष्ट्रपति शासन की अवधि 12 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, फिलहाल निलंबित अवस्था में रखी गई है।

पर्यवेक्षक की नियुक्ति क्या संकेत देती है?

भाजपा ने मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन एनडीए

विधायकों की बैठक बुलाई जा सकती है, जहां नए नेता के नाम पर मुहर लगेगी। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले ही सरकार का गठन कर लिया जाए।

नया मुख्यमंत्री कुकी या मैतेई-किस समुदाय से हो सकता है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री किस जातीय समूह से होगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी मैतेई समुदाय से मुख्यमंत्री बना सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कार्यकाल में असेंबली स्पीकर रहे सत्यव्रत सिंह, पूर्व मंत्री टीएच बिस्वजीत सिंह और के. गोविंद दास के नामों पर चर्चा हो रही है। ये तीनों नेता मैतेई समुदाय से आते हैं और संगठन व प्रशासनिक अनुभव रखते हैं।

कुकी समाज को साधने की तैयारी

बीते कुछ वर्षों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव और हिंसा ने मणिपुर को झकझोर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा इस बार संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में एक डिप्टी सीएम पद बनाया जा सकता है, जो कुकी समुदाय से होगा। इसका मकसद यह संदेश देना है कि सरकार सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती है।

कुकी विधायकों का दबाव बीजेपी के लिए चुनौती

भाजपा के भीतर भी हालात पूरी तरह सहज नहीं हैं। कुकी समुदाय से जुड़े विधायकों का कहना है कि उनके समाज में यह भावना है कि अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो सरकार में शामिल होना मुश्किल होगा। इस मांग को लेकर कुकी विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व से साफ शब्दों में बात रखी है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व हर कदम बेहद सोच-समझकर उठा रहा है।

क्या मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी मांग उठी है?

इन सबके बीच कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो मणिपुर को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर होगा और हालात संभालने में आसानी होगी। हालांकि इस विकल्प पर फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

आखिर बीजेपी किस रास्ते पर जाएगी?

कुल मिलाकर भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जातीय संतुलन साधने की है। पार्टी मैतेई मुख्यमंत्री और कुकी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के जरिए राज्य में स्थिर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि भाजपा किस चेहरे पर भरोसा जताती है और मणिपुर को नई राजनीतिक दिशा मिलती है या नहीं।

कोहरे में फिर से डूबेगा प्रदेश, इन 23 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी; लखनऊ रहा सूबे में सबसे गर्म

लखनऊ (एजेंसी)।

यूपी में एक बार फिर से कोहरे का साया दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में घना कोहरा दिख सकता है। मौसम में लगातार बदलाव जारी है। रविवार व सोमवार को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस बीच कई जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चलीं। सोमवार को अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर में सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। वहीं बहराइच, अयोध्या, अमेठी, कुशीनगर, मुजफ्फर नगर, मेरठ में दृश्यता 50 मीटर ने नीचे दर्ज हुई।

मौसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि में बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 23 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नए विकसित

हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी से शुरू हुई बूंदाबांदी का दायरा मंगलवार को बुदेलखंड, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज मंडल तक पहुंचेगा। प्रदेश में यह बदलाव 4 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद कोहरा छंटेगा और तापमान में हल्की गिरावट आएगी।

यहां है ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में।

घना से बहुत घना कोहरा की संभावना

देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में।

विक्षोभ का असर, लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे गर्म रहा लखनऊ

फरवरी की शुरूआत राजधानी में गर्म मौसम के साथ हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। सोमवार को दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी तेज उछाल देखने को मिला, जिससे ठंड का असर कमजोर पड़ा।

सोमवार सुबह हल्के कोहरे के साथ हुई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, आसमान साफ होता गया। तेज धूप निकली और हवा में गर्माहट महसूस की गई। दोपहर के समय मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, जिससे लोगों को दिन में गर्मी का अहसास हुआ।

मौसम विभाग का पूवार्नुमान है कि मंगलवार को बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि सुबह के समय घना कोहरा भी छा सकता है।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि निचले क्षोभमंडल में पंजाब और हरियाणा के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी कारण राजधानी का पारा प्रदेश में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री की बढ़त के साथ 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री की उछाल के साथ 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

बीते तीन दिनों के तापमान में